साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

वर्ष : 5, अंक : 40 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 27 मई से 2 जून 2020 पेज : 4 कीमत : 3 रुपये

पर्यावरण : कोई सबक नहीं

> पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इस महामारी के चलते नए सिरे से सारी चीजें दुरुस्त करनी चाहिए थी. पर असल में, वह यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है कि पर्यावरण का विनाश पहले की तरह चलता रहे।

इस वक्त दुनिया की एक-तिहाई आबादी लॉकडाउन में है. आसमान नीला और नदियों का पानी साफ है. भालू, नीलगाय और हाथी शहरों की वीरान पड़ी सड़कों पर घूम रहे हैं. अगर पृथ्वी को फिर से हासिल करने की प्रकृति के इन संकेतों से जीवन की हमारी जानी-पहचानी व्यवस्था के उलट-पुलट होने का डर आपको सता रहा हो तो चिंता की कोई बात नहीं है. असल में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है कि पर्यावरण का विनाश पहले की तरह चलता रहे.

मंत्रालय को चाहिए था कि कोविड-19 महामारी के चलते वह अपने कदमों को रोककर नए सिरे से चीजें दुरुस्त करता. इसके विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हैं कि जानवरों से इंसानों में फैलनी वाली बीमारियों का रिश्ता काफी हद तक वन्य जैवविविधता के लिए प्राकृतिक वास के नष्ट होने से भी है. अब ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने वाले शानदार वनों, नदियों और अन्य पारिस्थितिकीय तंत्रों का जो कुछ बचा रह गया है उसको बचाने के लिए हमें अभी और किसी कारण की तलाश है. पर मंत्रालय की विभिन्न स्थायी समितियों के लिए मानो सब कुछ सामान्य है.

अप्रैल में ही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्लूएल) की स्थायी समिति ने असम के देहिंग पटकई हाथी अभयारण्य में कोयले के खनन को मंजूरी दे दी. उसने उत्तराखंड में यमुना पर लखवाड़-व्यासी बांध परियोजना के लिए बिनोग वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के साथ लगे 768 हेक्टेयर के वन को साफ करने की भी मंजूरी दे दी. उसने राष्ट्रीय पार्कों, अभयारण्यों और टाइगर कॉरिडोर से गुजरने वाले राजमार्ग, ट्रांसमिशन लाइन तथा रेलवे लाइन बनाने के सभी प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी.

पर्यावरण अधिवक्ता ऋत्विक दत्ता कहते हैं, भारत के संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों को इस वक्त यदि किसी चीज से डरने की जरूरत है तो वह है एनबीडब्लूएल के सदस्यों से. समिति का लक्ष्य तो वन्यजीवन की रक्षा करना है, पर वह उससे भटक गई है.

मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (एफएसी) भी उन परियोजनाओं पर विचार करती है और मंजूरी दे देती है जिन्हें कभी अस्तित्व में आना नहीं चाहिए था. इस महीने, एफएसी की एक उपसमिति ने यह सिफारिश की कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी बेसिन में एटालिन पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे देनी चाहिए. यह परियोजना एक ऐसे क्षेत्र में 1,150 हेक्टेयर वनभूमि को नष्ट कर देगी जहां तीन अलग-अलग जैव-भौगोलिक क्षेत्र मिलकर एक विशाल जैवविविधता वाले हॉटस्पॉट का निर्माण करते हैं.

यहां क्लाउडेड लेपर्ड और बाघ रहते हैं. इसी तरह भारत में पाए जाने वाले पक्षियों की किस्मों में से आधे से ज्यादा यहां हैं. इन समृद्ध जंगलों में विभिन्न दुर्लभ जीवजंतु और वनस्पति हैं. साल 2010 में खुद मंत्रालय ने इसे एक अक्षत इलाके की संज्ञा दी थी, जब जयराम रमेश मंत्री थे. पर अब उसे अरुणाचल प्रदेश सरकार और जिंदल एनर्जी के संयुक्त उपक्रम के रूप में तैयार होने वाली 3,097 मेगावाट की परियोजना के लिए नष्ट होने को छोड़ दिया गया है.

एटालिन परियोजना को लेकर न सिर्फ पर्यावरणवादी क्षुब्ध हैं बल्कि भूगर्भशास्त्री भी इशारा कर रहे हैं इन दो बांधो से जुड़े कई बड़े जोखिमों को नजरअंदाज कर दिया गया है. दिबांग तलहटी के पर्वत और घाटियां एक भूकंपीय सक्रिय इलाके के ऊपर बैठे हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण इस तलहटी की नदियों को पानी उपलब्ध कराने वाले ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं.

इसके कारण झीलें बन रही हैं जिनमें पानी किनारे से ऊपर बहने लगेगा और निचले इलाकों में भारी बाढ़ तथा भूस्खलन पैदा होगा. (साल 2013 में उत्तराखंड में आई प्रलयंकारी बाढ़ मंदाकनी नदी को पानी देने वाले चोरबारी ग्लेशियर के इसी तरह पिघलने का नतीजा थी.) दिबांग नदी नीचे ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है और किसी भी भूकंप या बाढ़ के घातक नतीजे नीचे असम की घनी आबादी वाले तटीय इलाकों तक महसूस किए जाएंगे. जलवायु परिवर्तन से आने वाली नई चुनौतियों को देखते हुए मंत्रालय को तो और सावधानी बरतनी चाहिए थी.

लेकिन एफएसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, इसी से यह साफ हो जाता है कि उसकी प्राथमिकताएं कितनी विकृत हो गई हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया था कि ये परियोजनाएं पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और विकास को बढ़ावा देंगी. लेकिन पर्यावरण का बचाव कैसे होगा? उधर एटालिन और ब्रह्मपुत्र नदी पर अन्य सभी परियोजनाएं दरअसल इस नदी के पानी पर कब्जे को लेकर भारत-चीन के बीच की होड़ का प्यादा बन गई हैं.

कोविड-19 महामारी याद दिलाती है कि दुनिया आपस में कितनी जुड़ी हुई है और उसकी जटिलता पर हमारा राजनीतिक एवं आर्थिक नियंत्रण कितना कमजोर है. इसके बावजूद पर्यावरण मंत्रालय जानबूझकर भूल जाने की आदत से बाज नहीं आ रहा.

तापमान बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग

एक हफ्ते में राज्य में तापमान बढ़ने के साथ ही जंगल में आग की घटनाएं भी बढ़ीं। इस वर्ष फायर सीजन में 23 मई तक गढ़वाल के 11.25 हेक्टेअर, कुमाऊं के 36.05 हेक्टेअर के साथ वन्यजीव संरक्षित 4.04 हेक्टेअर क्षेत्र मिलाकर कुल 51.34 हेक्टेअर जंगल की आग की जद में आए।

27 मई तक आग का दायरा 110.53 हेक्टेअर क्षेत्र तक पहुंच गया। इसमें गढ़वाल के 52.75 हेक्टेअर जंगल, कुमाऊं के 52.62 हेक्टेअर और वन्यजीव संरक्षित 5.16 हेक्टेअर क्षेत्र शामिल है। पिछले तीन दिनों (25,26,27 मई) में पौड़ी सिविल वन (28 हेक्टेअर), अल्मोड़ा (22 हेक्टेअर), रानीखेत मृदा संरक्षण (8.25 हेक्टेअर), पिथौरागढ़ (13.3 हेक्टेअर) समेत रुद्रप्रयाग, नई टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर, रामनगर, मसूरी, लैंसडोन, अपर यमुना (देहरादून), गढ़वाल, बद्रीनाथ, राजाजी रिजर्व, कार्बेट रिजर्व, नंदादेवी नेशनल पार्क आग की चपेट में आए। आग से अब तक 2,85,805 रुपये के नुकसान का आंकलन किया गया। हालांकि इसके साथ ही जंगल में औषधीय वनस्पतियों, छोटे-छोटे जीव-जंतुओं का भी नुकसान होता है। जिसका आंकलन मुश्किल है।

देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 21-27 मई के बीच राज्य में ज्यादातर जगहों पर औसत तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। देहरादून में 21 मई को तापमान 37 डिग्री, 22 मई- 39 डिग्री, 23 मई- 39 डिग्री तक दर्ज किया गया। 24 मई को पारा 40 के उपर चला गया। 25,26,27 मई को भी तापमान 40 के कुछ उपर ही रहा। जबकि सामान्य तापमान 35 डिग्री के आसपास होता है। इसी दौरान राज्य के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ीं।

अल्मोड़ा में जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के वैज्ञानिक डॉ संदीपन कहते हैं कि प्री-मानसून हीटवेव के चलते हर साल इस समय तापमान बढ़ता है। वह बताते हैं कि पिछले 4-5 दिनों में हवा में गर्मी ज्यादा बढ़ी है। इसका असर सेंट्रल इंडिया में रहता है। ऐसे में यदि आंधी आती है तो गर्मी से राहत मिलती है। इस समय गर्मी बढ़ने से देश के पश्चिमी हिस्से से लेकर पूर्वी हिस्से तक हवा का दबाव कम होता है जिससे मानसून को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। डॉ संदीपन कहते हैं कि ग्लोबल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी वजहों से हीटवेव की फ्रीक्वेंसी और तीव्रता पिछले 10-15 वर्षों में बढ़ी है।

जंगल की आग को लेकर डॉ संदीपन कहते हैं कि चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों जैसे ओक के जंगलों की तुलना में चीड़ के जंगलों की सतह उल्लेखनीय रूप से अधिक गर्म होती है। इस पर अभी शोध जारी है। चीड़ की पत्तियां भी ज्वलनशील होती हैं। उत्तराखंड में चीड़ के जंगल बहुतायत में हैं इसीलिए यहां आग की घटनाएं अधिक होती हैं। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि जंगल की आग की ज्यादातर वजह मैनमेड होती है।

पौड़ी के डीएफओ आकाश वर्मा कहते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जंगल फिर भी बेहतर स्थिति में हैं। (पिछले वर्ष 25 मई तक राज्य के 1590 हेक्टेअर जंगल आग की चपेट में आ चुके थे।) पौड़ी में 23-24 मई को सिविल फॉरेस्ट में आग लगी। आकाश वर्मा के मुताबिक खेतों के पास लोगों ने ये आग लगाई थी। 23 मई को आग पर काबू पा लिया गया लेकिन 24 मई को फिर सुबह आग लगी। हवा तेज़ होने की वजह से आग पर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ी। मंगलवार को बारिश होने के साथ ही मिट्टी में नमी आ गई है, जिससे जंगल को राहत मिली।

डीएफओ आकाश वर्मा कहते हैं कि कोरोना के चलते जरूरत पड़ने पर वन विभाग की गाड़ियां गांवों में राशन पहुंचाने जैसे कार्यों में इस्तेमाल की जा रही हैं। वन विभाग के कंट्रोल रूम का इस्तेमाल भी कोरोना से जुड़ी सूचनाओं के लिए किया जा रहा है। पौड़ी के सिविल वन में लगी आग पर काबू पाने में गढ़वाल रेंज के स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई गई।

उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक जयराज कहते हैं कि लॉकडाउन के शुरुआती समय में वन विभाग के कर्मचारियों की कोरोना रोकथाम के लिए ड्यूटी लगाई गई। जंगल में आग की घटनाएं सामने आने लगीं तो ये ड्यूटी हटा ली गई। इस समय वन विभाग का ज्यादातर स्टाफ जंगल की सुरक्षा में तैनात है।

वायरल तस्वीरों के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर जंगल में आग लगने की झूठी तस्वीरें लगायी गई हैं। इनमें से ज्यादातर तस्वीरें या तो वर्ष 2016-17 में राज्य के जंगलों की आग की हैं या दूसरी जगहों से ली गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर जंगल में आग को लेकर स्थिति स्पष्ट की है और कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जंगल में आग का दायरा अब तक करीब 5 प्रतिशत ही है।

अगले कुछ दिन राज्य के जंगलों पर मौसम की मेहरबानी रहेगी। देहरादून में आज भी बादल छाए हैं। तेज़ हवाएं चल रही हैं। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने 28 मई से राज्य में ज्यादातर जगहों पर बारिश की संभावना जतायी है। मैदानी क्षेत्रों में तेज़ हवा-आंधी का अनुमान भी जताया गया है। बारिश से मिट्टी नम होगी तो आग फैलने का खतरा टलेगा।

क्या पानी से हटाया जा सकता है कोरोनावायरस, वैज्ञानिकों ने की रिसर्च

वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेवार सार्स-सीओवी-19 वायरस सहित कोरोनावायरस, सीवेज और पीने के पानी में अधिक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाने का प्रयास किया कि क्या पानी को ट्रीटमेंट के जरिए वायरस मुक्त किया जा सकता है?

नोवल कोरोनोवायरस को पानी से हटाना जरुरी ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके

शोधकर्ताओं ने बताया कि वायरस सूक्ष्म पानी की बूंदों से, वाष्पीकरण या स्प्रे के माध्यम से हवा में प्रवेश करते हैं। यह शोध एनवायर्नमेंटल साइंस - वाटर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं की इस टीम में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, रिवरसाइड में रासायनिक और पर्यावरण इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैजोउ लियू और सालेर्नो विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर विन्केन्ज़ो नादादेओ शामिल हैं।

शोधकर्ताओं के मुताबिक 2003 में हांगकांग में सार्स के प्रकोप के दौरान सीवेज के रिसाव से पानी की छोटी बूंदे एरसोल के माध्यम से हवा में पहुंच गई थी, जिसके कारण इस बीमारी के मामले बढ़ गए थे। हालांकि कोविड-19 के अभी तक सामने आए मामलों में कोई भी सीवेज रिसाव होने के कारण नहीं हुआ है, नोवल कोरोनोवायरस संक्रमित व्यक्ति के निकट आने से फैलता है।

नोवल कोरोनोवायरस पानी की लाईन, जैसे फुहारे के माध्यम से हवा में फैल सकता है जिसे शॉवरहेड्स एयरोसोल ट्रांसमिशन कहा जाता है। इस तरह के माध्यम बैक्टीरिया के संपर्क का एक प्रमुख स्रोत माने जाते हैं।

अध्ययन के मुताबिक, अधिकांश वाटर ट्रीटमेंट पीने और अपशिष्ट जल दोनों में प्रभावी ढ़ंग से कोरोनावायरस को मारने या हटाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पानी को साफ करने के लिए उपयोग किया जाने वाला केमिकल हाइपोक्लोरस एसिड या पेरासिटिक एसिड के साथ ऑक्सीकरण होने, और पराबैंगनी विकिरण के साथ-साथ क्लोरीन द्वारा कोरोनावायरस को मार दिया जाता है। वेस्टवाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का उपयोग होता हैं, जो ठोस, अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने के साथ-साथ विषाणुओं को छान देता है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि संक्रमण वाले स्थानों में मौजूदा वाटर ट्रीटमेंट और वैस्ट्वॉटर ट्रीटमेंट के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाना चाहिए। अस्पताल, सामुदायिक क्लीनिक और नर्सिंग होम जैसे स्थानों से सीवेज के द्वारा कोरोनवायरस वाटर ट्रीटमेंट तक पहुंच सकता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, ऊर्जा-कुशल, प्रकाश-उत्सर्जक, डायोड-आधारित, पराबैंगनी प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि पानी कीटाणुरहित हो जाए।

घरों में जीवाणुनाशक, विषाणुनाशक और कीटाणुनाशक के अधकि उपयोग से पर्यावरण में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीवाणुओं की वृद्धि होने की आशंका है। ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से साफ किए गए जल की सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए ताकि उसका असर प्राकृतिक जलमार्गों पर न हो। लियू और नादादेओ ने रसायनज्ञों, पर्यावरण इंजीनियरों, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को सुरक्षित पेयजल और स्वस्थ जलीय वातावरण के लिए व्यावहारिक समाधान विकसित करने का आग्रह किया है।

विकासशील देशों और अत्यधिक विकसित देशों के कुछ क्षेत्रों के अंदर, जैसे कि ग्रामीण और गरीब समुदाय, जिनके पास पानी में से आम प्रदूषणों को हटाने के लिए बुनियादी चीजों की कमी है, ऐसे में वे सार्स-सीओवी-19 को कैसे हटा सकते हैं। ऐसे स्थानों पर वैश्विक व्यापार और यात्रा के माध्यम से आसानी से कोविड-19 फैल सकता है। लियू और नादादेओ सुझाव देते हुए कहते हैं कि, विकसित देशों की सरकारों को जहां भी जरूरत हो, वहां पानी और सफाई व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए।

अब यह स्पष्ट है कि वैश्वीकरण से स्वास्थ्य के लिए नए खतरे पैदा होते है। जहां पानी और सफाई व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, वहां नए वायरस मिलने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। विकसित देशों की सरकारों को विकासशील देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं, पानी और सफाई व्यवस्था आदि में सहयोग करना चाहिए, ताकि उनके अपने देशों के नागरिकों की भी रक्षा हो सके।

तितलियों की संख्या में बढोत्तरी से पर्यावरण को होगा बड़ा फायदा

नई दिल्ली. देशभर में लॉकडाउन करके जहां लोगों को कोरोना महामारी से बचाने की कोशिश की जा रही है. वहीं इसका एक बहुत ही सकारात्मक पहलू सामने आया है. पिछले दो महीने से चल रहे लॉकडाउन में तितलियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है. जिसे वैज्ञानिक आने वाले दिनों में प्रकृति के लिए वरदान बता रहे हैं।

वैज्ञानिकों का कहना है कि पर्यावरण इंडिकेटर तितलियां आने वाले समय में अच्छी स्थितियों की ओर इशारा कर रही हैं. उनका कहना है कि इस बार तितलियों की ऐसी प्रजातियां भी देखी गई हैं जो लंबे समय से प्रदूषण के कारण विलुप्त चल रही थीं. लिहाजा इनकी संख्या बढ़ना पर्यावरण के साथ ही सभी जीव-जंतुओं के लिए भी लाभदायक साबित होगा।

दिल्ली बायोडायवर्सिटी पार्क के जीव विज्ञानी फैय्याज खुदसर कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद वायु प्रदूषण में कमी आने से इस बार तितलियों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हुई है. सबसे ज्यादा फायदा सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां बंद होने से हुआ है क्योंकि पेट्रोल में भारी मेटल होते हैं और जब गाड़ियां चलती है तो हेवी मेटल पॉल्युशन होता है. ये हेवी मेटल रस पैदा करने वाले पौधों के तनों पर जम जाते हैं और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते हैं. इसका सीधा-सीधा असर तितलियों की संख्या पर पड़ता है क्योंकि तितलियां उन पौधों पर ही निर्भर होती हैं।

फैय्याज कहते हैं लम्बे समय से भारत प्रदूषण की मार झेल रहा है. हेज़ और स्मोक तितलियों के लिए जानलेवा होता है लेकिन मार्च के अंतिम सप्ताह से गाड़ियां, फैक्ट्री, मिलें आदि पूरी तरह बन्द होने से आसमान साफ हुआ है. हेज़ और स्मोक का स्तर काफी घटा है. बता दें कि जब भी हेज़ और स्मोक होता है तो लार्वा के विकास का समय बढ़ जाता है. साथ ही कैटरपिलर की मृत्यु दर बढ़ जाती है. ऐसे में या तो हेल्दी तितलियां नहीं निकल पाती या फिर तितलियां निकल ही नहीं पाती।

फैय्याज बताते हैं कि तितलियां पर्यावरण का सबसे अच्छा इंडिकेटर होती हैं. ये पोलीनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं. ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ज़रूरी तत्वों को पहुंचाने का काम करती हैं. इनकी तादाद बढ़ने का अर्थ है कि इस बार पर्यावरण को काफी फायदा हुआ है. इस बार बायोडायवर्सिटी पार्क में ही ग्रासलैंड और वुडलैंड, पायनियर तितलियों की संख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ी है. ब्लू जे, ब्लू मोरमन, साउथ बर्डविंग, ट्री निम्फ, अंडमान क्रो जो नहीं दिखाई देती थी, अब दिख रही है।

अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में तितलियों पर काम कर रहीं वैज्ञानिक आयशा सुल्ताना कहती हैं कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पर्यावरण के लिए एक टाइगर से भी ज्यादा जरूरी तितलियां होती है. बेहद ही छोटे इन जीवों का पर्यावरण और पेड़-पौधों को आगे बढाने में अहम योगदान है. अगर तितलियां न हों तो पांच साल के अंदर प्रकृति से खाना ही खत्म हो जाएगा. ये तितलियां फूड चेन बनाती हैं. ये पूरी दुनिया के लिए ऐसा आधार बनाती हैं, जिससे उन्हें उनका हैबिटेट मिलता है. इन तितलियों के अलग अलग पौधे होते हैं जिन पर ये अंडे देती हैं।

कोरोना के बीच आया टिड्डी संकट बेहद गंभीर, फसलों को हो सकता है भारी नुकसान

पश्चिमी भारत में टिड्डी दल के हमलों को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि यह एक बहुत ही खराब समय पर आया गंभीर मामला है जब देश पहले ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रसार से जूझ रहा है, इससे फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है।

पर्यावरण मंत्रालय के वन्यजीव इंस्पेक्टर जनरल सौमित्र दासगुप्ता ने कहा कि ये रेगिस्तानी टिड्डे थे जिन्होंने भारत में बड़ी संख्या में हमला किया और इससे फसलों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। टिड्डियां हमारे देश में सामान्य हैं लेकिन यह हमला बहुत बड़ा है।

उन्होंने कहा कि टिड्डियों के हमले को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है, इससे कृषि मंत्रालय और संबंधित राज्यों को निपटना होगा। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि टिड्डी हमला पूर्वी भारत में भी फैलने का खतरा है और इससे खाद्य सुरक्षा के लिए संकट बढ़ गया है।

राजस्थान टिड्डियों से सबसे ज्यादा प्रभावित

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार ये टिड्डी दल फिलहाल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में सक्रिय हैं। अभी तक राजस्थान टिड्डी दलों के हमले से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य है। बता दें कि जयपुर में लगभग 28 साल बाद टिड्डी दल ने दस्तक दी है। इससे पहले 1993 में टिड्डियों ने जयपुर में फसलों को चट कर दिया था। यहां सोमवार सुबह टिड्डियों का एक बडा झुंड परकोटा क्षेत्र में बड़ी चैपड़ और आस-पास के इलाकों में देखा गया था।

उत्तर प्रदेश में कई जिलों में टिड्डी दल से खतरा

राजस्थान के बाद टिड्डी दल उत्तर प्रदेश में भी कोहराम मचा सकता है। यूपी के आगरा, लखीमपुर खीरी, मेरठ, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, झांसी और कानपुर देहात में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है।

टिड्डे की एक प्रजाति रेगिस्तानी टिड्डा सामान्यतः सुनसान इलाकों में पाया जाता है। जब हरे-भरे घास के मैदानों पर कई सारे रेगिस्तानी टिड्डे इकट्ठे होते हैं तो ये निर्जन स्थानों में रहने वाले सामान्य कीट-पतंगों की तरह व्यवहार नहीं करते बल्कि एक साथ मिलकर भयानक रूप अख्तियार कर लेते हैं।

आसमान में उड़ते हुए इन टिड्डी दलों में दस अरब तक टिड्डे हो सकते हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैले हो सकते हैं। ये झुंड एक दिन में 200 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008